[श्री राम विचार शास्त्री]

कमेटी ने भी सिफारिश की थी कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये । जब भी इसके बारे में सदन में सवाल उठता है सरकार चुप्पी साध लेती है, कोई न कोई बहाना बना कर चिकनिया पार हो जाती है, निक्ल भागती है, उस रिंग से निकल जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्हों आप नहीं करना चाहते हैं इसके पीछे कारण क्या है ? आप आई० डी० पी० एल० चला सकते हैं तो क्यों इनको भी आप नहीं चला सकते हैं । यह अलग बात है कि वह घाटे में चल रहा है । बहुत से सार्वजनिक संस्थान है, कारखाने हैं जो बदइंतेजामी की वजह से, गलत नीतियों की वजह से, जो उनको चलाने वाले हैं पूंजीपतियों के साथ उनकी साठगांठ होने की वहज से, वे घाटे में चलते हैं लेकिन बहुत से ऐसे भी कारखाने हैं जो नफे में चलते हैं । आई० डी० पी० एल० जब आप चला सकते हैं तो फिर दूसरी दवा कम्पनियां आप क्यों नहीं चला सकते हैं । बार बार इस काम से आप इन्कार क्यों कर रहे हैं । राष्ट्रीयकरण आप करें तो निश्चित रूप से काम ठीक होगा ।

ऐसी दवाएं भी बड़ी संख्या में आज देश में बिक रही हैं जो टाइम बार्ड हो गई होती है, जिन का समय बीत गय होता है, जिन की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई होती है । उनको भी आप पकड़िये उन से भी बहुत ज्यादा लोग मरते हैं । मैं चाहता हूं कि आप एक व्यापक विधेयक इन सब बातों के लिए लाएं । ये चीजें इस विधेयक में नहीं हैं । इस में केवल नकली दवाओं को रोकने की आपने व्यवस्था की है जो अच्छी बात है इस काम में सब आपके साथ सहयोग करेंगे, जनता भी आपके साथ सहयोग करेगी । लेकिन कमियों के बावजूद आप इस कानून को ठीक से लागू करें । तभी कुछ जनता का भला हो सकेगा, गरीबों का और दवाइयां इस्तेमाल करने वालों का भला हो सकेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Minister will reply on Monday. Now, the House will take up Private Members' Legislative Business.

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FORTY-NINTH REPORT

SHRI T.R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move:

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th October, 1982."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Forty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 6th October, 1982."

The motion was adopted.